अध्यक्ष महोदय: उन्होंने जवाब तो दे दिया है ।

श्री फूल चन्द वर्मा: गोल-मोल जवाब दिया है ।

अध्यक्ष महोदय: जवाब गोल-मोल भी होता है ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर: मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वेनोडियन धातु जो है जोकि भारी मात्रा में फासिल है वह फसल पर आ जाती है--इसके सम्बन्ध में भी क्या आपको कोई जानकारी है? यदि हां, तो उसको रोकने के लिए आप कोई उपाय कर रहे हैं?

SHRI CHARANJIT CHANANA: After January when this instrument starts operating in the factory, then there will be no pollution at all. When 95 per cent of the pollution is eliminated then the question of this thing going and damaging the crop will not arise at all.

श्री मूलचन्द डागा: मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भी ऐसे उद्योग लगाए जाते हैं जिनके कारण प्रदूषण पैदा होता है--जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण--उनको लगाने से पहले ही एन्टी पोल्यूशन प्लान्ट क्यों नहीं लगाए जाते हैं ताकि प्रदूषण पैदा ही न हो? यह कानून बना हुआ है कि इण्डस्ट्री लगने से पहले प्रदूषण की रोक थाम का इन्तजाम किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सजेस्चन है ।

Estimated Rise in Educated unemployed by 1983

+

*330. SHRI RAM VILAS PASWAN:
SHRI S. B. SIDNAL:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the estimated rise in the figure of educated unemployed by 1983; and

(b) the steps contemplated by Government to provide employment opportunities during the Sixth Plan period to tackle the unemployment problem in the country?

THE MINISTER OF PLANNING AND LABOUR (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) The draft plan 1978-83 prepared by the Planning Commission estimated that the number of educated unemployed would rise by 6.89 lakhs between 1978—83. However, these estimates are under revision.

(b) One of the objectives of the draft Sixth Plan (1980—85) is to achieve a progressive reduction in the incidence of poverty and unemployment. The new Plan is still under formulation.

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय हम यह सोच रहे थे कि मंत्री महोदय ने जो लिखित रूप से जवाब दिया है उस में कुछ मिसप्रिंट हो गया है लेकिन उनके पढ़ने पर भी हम ने वही बात सुनी । **(व्यवधान)**

श्री नारायण दत्त तिवारी: बेरोजगारों की संख्या 6.89 लाख बढ़ जाएगी ।

श्री राम विलास पासवान: अच्छा, सर्वप्रथम, जहां तक मेरी जानकारी है ये जो आंकड़े आप उपलब्ध कराते हैं वे आप रोजगार दफतरों से कर के करते हैं जिनकी कि कोई विश्वसनीयता नहीं है । रोजगार दफतरों में गांवों के लोग प्राय: अपना नाम दर्ज ही नहीं करवाते हैं । इसलिए इस से आप हमेशा धोखा खायेंगे ।

मैं आप से पूछना चाहता हूं कि अभी शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है और आपने जो छठी पंचवर्षीय योजना बनायी है उसमें कितने शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की आपने योजना बनायी है? उन में से कितनों को आप टेक्निकल में और कितनों को नान-टेक्निकल में एबजोर्ब करेंगे?

जब तक आप संख्या नहीं बतलायेंगे तब तक यह हम लोगों के शब्दों में अस्पष्ट और अध्यक्ष महोदय इनके शब्दों में स्पष्ट बात होगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी: श्रीमान्, मैं स्पष्टवादिता का बड़ा आदर करता हूं । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आंकड़े मैंने विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत किये हैं वे आंकड़े एम्पलाएमेंट एक्सचेंजों या रोजगार दफतरों

द्वारा दिये हुए आंकड़े नहीं हैं। यह जो देश की एक सर्वमान्य संस्था राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है, नेशनल सेम्पल सर्वे है, उसके द्वारा ये आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं।

जहां तक माननीय सदस्य ने यह जानकारी प्राप्त करनी चाही है कि हमारे देश में बेरोजगारों की कुल संख्या क्या है, तो जो इस संगठन के द्वारा सर्वेक्षित किये गये आंकड़े हैं वे इस प्रकार हैं--अनुमानतः देहाती क्षेत्रों में 12.8 मिलियन और शहरी और नगरीय क्षेत्रों में 4.1 मिलियन बेरोजगार हैं।

जहां तक पढ़े-लिखे बेरोजगारों का प्रश्न है, हमारे जो एम्पलाएमेन्ट एक्सचेन्ज हैं केवल उनमें ही विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारों का पंजीकरण किया जाता है। दिसम्बर, 1979 तक उनकी संख्या 7.3 मिलियन थी। इनकी संख्या रोजगार दफ्तरों से लेने की हमारी विवशता है क्योंकि इनके पंजीकरण का यही एकमात्र माध्यम है।

जहां तक विद्वान सदस्य ने भविष्य के लिए आंकड़े जानने चाहे हैं तो मैं यह धृष्टता तो नहीं करूंगा कि इस सम्मानित सदन के सामने भविष्य के लिए ऐसे तथाकथित लिखित और निश्चित आंकड़े प्रस्तुत करूं जिनकी कि केवल संभावना के आधार पर कल्पना ही की जा सकती है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न बड़ा आधारभूत प्रश्न है। शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए हमने विद्वानों का एक कार्यकारी ग्रुप या वर्किंग ग्रुप बनाया है। उस कार्यकारी दल की संस्तुतियों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।

साथ ही साथ माननीय सदस्यों के संमुख छटी योजना का प्रारूप भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था। उस में उन विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख है जिनके अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारी और अन्य बेरोजगारी को दूर करने के कुछ कार्यक्रमों को हम कार्यान्वित करना चाहते हैं। राज्य प्रशासनों द्वारा चलायी गयी योजनाएं भी हैं। लेकिन उनमें मुख्य योजना जिसे ट्राईसम योजना कहते हैं वह है। यह योजना देहाती क्षेत्रों में युवकों के टेक्निकल प्रशिक्षण के कार्यक्रम की योजना है। इसे ट्रेनिंग आफ रूरल यूथ्स फार सेल्फ एम्प्लाएमेंट कहते हैं। इस योजना को अधिक प्रभावकारी रूप से प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक जिले में एक एम्प्लाएमेंट जेनरेशन सेन्टर बनाने की बात इस में कही गयी है जो जिलों में बेरोजगारी के निवारण के केन्द्र बनेंगे उनमें व्यापार, बैंकिंग, युनिवर्सिटी और हर प्रकार के लोगों के प्रतिनिधियों को मिला कर के विचार किया जाएगा। कि प्रत्येक जिले में कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें स्वरोजगार के आधार पर कार्यान्वित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार से तो प्रश्न पूरा नहीं हो पाएगा।

एक माननीय सदस्य: आप पटल पर रख दीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी: आप आज्ञा दें तो बाद में विस्तृत विवरण दे सकता हूं। बैंकों से भी कहा जा रहा है। प्रत्येक बैंक की शाखा से दो बेरोजगार युवकों को ऋण देने की बात कही गई है, इस माध्यम से कुल मिलाकर 60 हजार युवकों को रोजगार मिलने वाला है। जब सारा विवरण आएगा तब पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

श्री रामविलास पासवान: मैंने सीधा सवाल पूछा था, प्लानिंग मंत्री हैं, कि जब तक साफ योजना नहीं बनेगी तब तक रोजगार की बात तो दूर रही बेरोजगारों की योजना ही आप बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास कोई योजना है और आप कितने लोगों को भविष्य में रोजगार देने जा रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने पिछली पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया था, बेरोजगारी के संबंध में, क्या उस लक्ष्य की प्राप्ति से आप संतुष्ट हैं और यदि नहीं संतुष्ट हैं तो यह जो शिक्षा पद्धति है जिसे व्यावसायिक शिक्षा पद्धति के रूप में भी सुधारा गया है, उसके रिजल्ट भी आपके सामने हैं तो क्या आप भविष्य में कोई नई शिक्षा पद्धति, जो बुनियादी परिवर्तन कर सके, जो रोजगारोन्मुख शिक्षा दे सके, इस तरह की कोई शिक्षा पद्धति लागू करने का विचार कर रहे हैं क्या?

श्री नारायण दत्त तिवारी: इस प्रश्न पर भी विचार हो रहा है । राज्य सरकारें भी विचार कर रही हैं । अभी गुजरात सरकार ने कक्षा 10 पास लोगों को प्रोफेशन, ट्रेड में लगाने की कोशिश की है। इसी तरह से आंध्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों ने भी अपनी योजनाएं प्रस्तुत की हैं।

SHRI S. B. SIDNAL: I would like to know whether for solving the problem of unemployment in the coming years, the Government has made a plan other than this regular employment plan through imparting technical education or something like that.

MR. SPEAKER: He has already replied to that part.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Some time ago the then Prime Minister, Shri Morarji Desai, had made a public statement to the effect that he had a magic formula by which within 10 years he would wipe out all unemployment in this country. Mr. Ram Vilas Paswan was also a member of the Ruling Party at that time. I would like to know whether the hon. Minister, Mr. Tiwari, is in a position to tell us whether there was any basis to this pronouncement made by Shri Morarji Desai at that time or whether it is not a fact that this too was another pronouncement merely for public consumption, but that there is no work done on this, nor was there a plan so to speak to clear this backlog of unemployment in 10 years and it was merely another pallative for public consumption.

MR. SPEAKER: Do you want to reply of that question?

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: It is difficult for me to answer any question on behalf of Mr. Morarji Desai, but there was nothing so specific in the earlier Plan draft by which we can say that it could eradicate unempoyment within a period of ten years. There is no such comprehensive plan that we have found.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Both the Chairman and the Deputy Chairman of the Planning Commission are here. Is it not a fact that during the Janata rule there was a specific programme for removing unemployment such as food-for-work, a crash programme for the educated unemployed, district industrial centres and a whole host of such programmes including Antyodaya? Is it a fact that this Government has decided either to scale down the allocations for such programmes or scrap them altogether? I would like to know the present state of these programmes. which were earlier followed.

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): I may inform the hon. Member that the food-for-work programme was decided upon in 1976.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: What about the other programmes? The Prime Minister cannot get up like this.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: He was not in the Government then.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: During the Janata rule, 4 million tonnes of foodgrains were allocated for the food-for-work programme. You have decided to cut it down to 1 1/2 million tonnes. Is it not a fact?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): The buffer stock was eaten up by the Janata Government. (*Interruptions*).

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: The hon. Member is very well aware that the food-for-work programme has now been expanded on a vast scale and is called the National Rural Unemployment Programme. It is proposed that in each of the 5,000 blocks of the country, about 1,000 unemployed will be given work. Even this year it has been extended and a Cash component has been added in the Budget proposals put

forward in this House. Apart from that, the tribal and Scheduled Castes component programmes are now going to cover the whole country. I think almost all of the programmes which the hon. Member mentioned are being strengthened and remodelled.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I asked whether it is a fact that the allocation of 4 million tonnes made under the Janata rule for the food-for-work programme has been reduced to 1 1/2 million tonnes, the district industrial centres have been scrapped, and the allocation for a crash programme for the educated unemployed has been removed. I do not want a speech.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: Nothing is being scrapped, all the schemes are being strengthened, whatever schemes were reasonable and practicable are being strengthened.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: He cannot say "reasonable". What is meant by reasonable?

MR. SPEAKER: You table a specific question, I will admit it.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: That is not the issue. The issue is whether 4 million tonnes has been reduced to 1-1/2 million tonnes under this rule, yes or no.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: Four million tonnes was for three years. Now it is 1.8 million tonnes for one year.

New Islander Aircraft for Coastal Patrol

*331. SHRI K. P. SINGH DEO: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Coast Guard and Navy have asked for the purchase of nine Islander aircraft for coastal patrol;

(b) whether Government would ensure that without in any-way jeopardising the security of the coasts of the country, the choice of the plane is such as may not make dependence on imported fuel a must; and

(c) if so, by what time a decision in this regard will be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) to (c). Proposals for the acquisition of aircraft for the Coast Guard Organisation are under consideration of the Government. The Government will take all aspects into consideration before coming to a final decision.

SHRI K. P. SINGH DEO: In view of the fact that the Coast Guards was set up by an Act of Parliament...

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Under the Janata rule.

SHRI K. P. SINGH DEO: You can have that satisfaction...of ensuring safety of navigation in our waters, protection of our off-shore installations, and fishing interests, salvage and pollution control measures, enforcement of national laws in our maritime zone including assistance to customs authorities in anti-smuggling operations and also for substantial increase in a number of activities in our maritime zone, and in view of the development of stretegic environments in the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal, I would like to know if the Government or the Coast Guards organisation appointed any technical evaluation committee to look into the most cost-effective aircraft for maritime surveillance, and if so, what were the types of aircraft which were evaluated. What were